

DHARAVI COMPILED MEDIA REPORT

19 Dec, 2024 – 20 Dec, 2024

 **Total Mention 31**

 Print	Financial	Mainline	Regional	Periodical
6	N/A	1	5	N/A
 Tv	Business	English	Hindi	Regional
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
 Online				

25


Print

No	Newspaper	Headline	Edition	Pg
1.	Free Press Journal	Can we dare hope for a more liveable Mumbai in 2025	Mumbai	24
2.	Navbharat	Relief to upper floor residents	Mumbai	4
3.	Khabre Aaj Tak	All tenement holders living in upper floors under Dharavi Redevelopment Scheme will be eligible for ...	Mumbai	2
4.	Navbharat Times	Dharavi's ineligible families will become house owners after 25 years	Mumbai	5
5.	Mid Day (Gujarati)	In Dharavi redevelopment, upper floor residents will also get space	Mumbai	1, 10
6.	Janmabhumi	Relief to upper floor residents in Dharavi	Mumbai	8

Free Press Journal • 20 Dec • Dharavi

Can we dare hope for a more liveable Mumbai in 2025

24 • PG

229 • Sqcm

182347 • AVE

251.68K • Cir

Top Left

Mumbai



MumbaiNaama

SMRUTI KOPPIKAR

Can we dare hope for a more liveable Mumbai in 2025?

A wishlist for Mumbai's future: challenges, needs, and the promise of better living. The dream of a liveable Mumbai should not remain a mere aspiration

The end of the calendar year is an apt time to take stock of key incidents that transpired, reflecting on the highs and lows of the past year, and creating a wishlist for the next. For Mumbai, the latter part is straightforward: we want, no, we demand a city that's liveable in every respect for everyone.

This means an improved city where tall skyscrapers do not dwarf life on the streets, affordable housing becomes a reality, and pavements are built and maintained for walkers to use safely. Roads should be free of potholes and rough surfaces. Public transport systems must be developed comprehensively, without prioritising the metro alone. We envision many more gardens and open spaces that are maintained and accessible to all, protected trees, and rejuvenated water bodies. Cultural life should flourish in clean, welcoming public arenas. Public schools and colleges in every neighbourhood must be comparable to private institutions, and markets must not encroach on pedestrian spaces. Traffic discipline should be strictly enforced by police personnel.

Further, projects must undergo climate and gender audits, and

the long-pending elections to the Brihanmumbai Municipal Corporation should ensure transparency and accountability. A fair deal in the Dharavi redevelopment that benefits its residents and the city, along with greater neighbourhood-level participation in governance, is essential. This exhaustive list is far from complete. It requires input from every community in Mumbai, but the core demand is simple: a liveable city that respects the life and dignity of its 18-19 million residents.

The modesty of these demands — basic pavements, clean air, functional buses — reflects the grim state of Mumbai's civic infrastructure. Even as we set our sights low, disappointment looms large. The question remains: why is it so difficult to make Mumbai liveable?

It is not for lack of resources. The BMC and allied bodies have substantial funds, among the richest municipal institutions globally. It is not a lack of imagination; Mumbaikars have built world-class start-ups, towering skyscrapers, and executed ambitious infrastructure projects like the 33-kilometre underground metro. Political will exists when it suits those in power, as evidenced by projects like the



Coastal Road and Atal Setu. Nor is it for lack of public interest; activists, citizens, and experts continuously strive to make the city better.

Despite these advantages, 2024 saw grim reminders of systemic failures. BEST buses, a lifeline for over three million commuters, faced accidents and financial losses, including cumulative debts of nearly ₹300 crore. Pedestrian safety remains perilous; roads and obstructed pavements pushed walkers into traffic, contributing to alarming fatality rates. Over 800 skyscrapers have been approved since 2008, yet af-

fordable housing remains elusive. MHADA's recent call for 2030 houses attracted over 1.3 lakh applicants, highlighting the acute housing crisis.

Environmental degradation adds to the woes. Thousands of trees were felled for projects, exacerbating the city's vulnerability to climate extremes. Air quality repeatedly hit hazardous levels, yet comprehensive action plans are lacking. Public safety also came under scrutiny with incidents like the Kurla BEST bus tragedy and the deadly hoarding collapse, exposing administrative negligence and corruption.

Can we dare to hope for a better 2025? Without hope, all is lost. Yet, hope must translate into action. We need accountable governance, sustainable urban planning, and active civic participation to realise our wishlist. The dream of a liveable Mumbai should not remain a mere aspiration but a shared responsibility and achievable goal.

Smruti Kopikar, senior journalist and urban chronicler, writes extensively on cities, development, gender, and the media. She is the Founder Editor of the award-winning online journal 'Question of Cities' and won the Laadli Media Award 2024 for her writing in this column.

Navbharat • 20 Dec • Dharavi
Relief to upper floor residents

4 • PG

160 • Sqcm

120174 • AVE

675K • Cir

Bottom Right

Mumbai Plus

Mumbai

ऊपरी मंजिल के निवासियों को राहत

धारावी में हायर-परचेज योजना पर उपलब्ध होगा सस्ता आवास

धारावीकरों को मिलेगा आधुनिक आवास

■ मुंबई, (सं). स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) के तहत धारावी पुनर्विकास योजना (डीआरपी) ने एक अद्वितीय नीति पेश की है, जो ऊपरी मंजिलों में रहने वाले निवासियों को शामिल करती है, जिससे यह महाराष्ट्र में सबसे समावेशी और मानव केंद्रित पुनर्विकास योजना होगी. राज्य सरकार के एक आदेश (जीआर) के अनुसार, 15 नवंबर 2022 तक धारावी में ऊपरी मंजिलों में रहने वाले सभी टेनेमेंट धारक हायर-परचेज योजना के तहत पुनर्वास के लिए योग्य होंगे. इस योजना के तहत टेनेमेंट धारकों को मुंबई में, लेकिन धारावी के बाहर, 300 वर्ग फीट का घर मिलेगा, जिसका किराया 25 वर्षों तक मामूली होगा, जिसके बाद वे इस यूनिट के मालिक बन जाएंगे. इस नीति में लचीलापन भी है, जिससे निवासी 25 वर्षों के भीतर किसी भी समय एकमुश्त भुगतान करके यूनिट की स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं. किराया और यूनिट की खरीद राशि को



डीआरपी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और एकत्र किया जाएगा. जीआर के अनुसार, केवल वही ऊपरी मंजिल के निवासी इस हायर-परचेज योजना के लिए योग्य होंगे, जो बिजली बिल, पंजीकृत विक्री या किराया समझौता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट जिसमें मंजिल का उल्लेख हो, या उस मंजिल के योग्य भूतल निवासी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जैसे दस्तावेज

हायर-परचेज योजना के तहत, धारावीकर आधुनिक आवास में जाएंगे, जिसमें निजी शौचालय और रसोई जैसी आवश्यक सुविधाएं होंगी. अधिकारी ने कहा कि इन भवनों का रखरखाव पुनर्वास के बाद 10 वर्षों तक डेवलपर द्वारा किया जाएगा, जिससे निवासियों पर वित्तीय बोझ कम होगा. इसके अलावा, भवनों के निर्मित क्षेत्र का 10% क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से विकसित किया जाएगा, जिससे आवासीय सोसायटियों के लिए स्थायी आय का स्रोत बनेगा.

प्रदान करेंगे. परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि ऊपरी मंजिलों के टेनेमेंट धारकों के मुद्दे को सुलझाकर, धारावी पुनर्विकास योजना ने समावेशी शहरी पुनर्विकास का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. इस पहल से जीवन स्तर में सुधार होगा. साथ ही निवासियों को स्वामित्व भी मिलेगा. जो मुंबई के शुग्गी पुनर्विकास प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू करती है.

Khabre Aaj Tak • 20 Dec • Dharavi

All tenement holders living in upper floors under Dharavi Redevelopment Scheme will be eligible for ...

2 • PG

228 • Sqcm

22839 • AVE

375K • Cir

Top Right

Mumbai

धारावी पुनर्विकास योजना के तहत ऊपरी मंजिलों में रहने वाले सभी टेनेमेंट धारक हायर-पर्चेस योजना के तहत पुनर्वास के लिए होंगे योग्य

मुंबई: स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) के तहत धारावी पुनर्विकास योजना (डीआरपी) ने एक अद्वितीय नीति पेश की है, जो ऊपरी मंजिलों में रहने वाले निवासियों को शामिल करती है, जिससे यह महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे समावेशी और मानवकेंद्रित पुनर्विकास योजना बन गई है।

परंपरागत रूप से, झुग्गी-बस्तियों में ऊपरी मंजिलों को अवैध माना जाता था और उन्हें पुनर्विकास योजनाओं से बाहर रखा जाता था। इसके परिणामस्वरूप, इन निवासियों को पूरी तरह से विस्थापित होना पड़ता था, जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचता था। ये ऊपरी मंजिल के निवासी अक्सर अन्य झुग्गी-बस्तियों में चले जाते थे, जिससे नई अवैध संरचनाएँ बन जाती थीं और विस्थापन का यह सिलसिला जारी रहता था। इस समस्या का समाधान करने और मुंबई को झुग्गी-मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास योजना के तहत एक सोच-समझकर रणनीति बनाई है, जो ऊपरी मंजिलों में रहने वालों के लिए आवास की व्यवस्था करती है। 4 अक्टूबर 2024 को जारी सरकार के आदेश के अनुसार, 15 नवम्बर 2022 तक धारावी में ऊपरी

मंजिलों में रहने वाले सभी टेनेमेंट धारक हायर-पर्चेस योजना के तहत पुनर्वास के लिए योग्य होंगे। इस योजना के तहत, टेनेमेंट धारकों को मुंबई में, लेकिन धारावी के बाहर, 300 वर्ग फीट का घर मिलेगा, जिसका किराया 25 वर्षों तक मामूली होगा, जिसके बाद वे इस यूनिट के मालिक बन जाएंगे। इस नीति में लचीलापन भी है, जिससे निवासी 25 वर्षों के भीतर किसी भी समय एकमुश्त भुगतान करके यूनिट की स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। किराया और यूनिट की खरीद राशि को डीआरपी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और एकत्र किया जाएगा।

केवल वही ऊपरी मंजिल के निवासी इस हायर-पर्चेस योजना के लिए योग्य होंगे, जो बिजली बिल, पंजीकृत विक्री या किराया समझौता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट जिसमें मंजिल का उल्लेख हो, या उस मंजिल के योग्य भूतल निवासी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जैसे दस्तावेज प्रदान करेंगे।

‘हायर-पर्चेस योजना के तहत, धाराविकर आधुनिक आवास में जाएंगे, जिसमें निजी शौचालय और रसोई जैसी आवश्यक सुविधाएँ होंगी, जिससे सम्मान, गोपनीयता

और जीवन स्तर में सुधार होगा,’ डीआरपी-एसआरए अधिकारी ने कहा कि इन भवनों का रखरखाव पुनर्वास के बाद 10 वर्षों तक डेवलपर द्वारा किया जाएगा, जिससे निवासियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इसके अलावा, भवनों के निर्मित क्षेत्र का 10% क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से विकसित किया जाएगा, जिससे आवासीय सोसायटियों के लिए स्थायी आय का स्रोत बनेगा। आधुनिक टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, हरियाली, स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षिक संस्थान और बच्चों और परिवारों के लिए खेल और मनोरंजन के स्थान होंगे। ऊपरी मंजिलों के टेनेमेंट धारकों के मुद्दे को सुलझाकर, धारावी पुनर्विकास योजना ने समावेशी शहरी पुनर्विकास का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ‘यह पहल न केवल जीवन स्तर में सुधार करती है, बल्कि निवासियों को स्वामित्व और गर्व की भावना भी प्रदान करती है, जो मुंबई के झुग्गी पुनर्विकास प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू करती है,’ डीआरपी-एसआरए अधिकारी ने कहा। हजारों परिवार, जो सालों से असुरक्षित जीवन जी रहे थे, अब एक स्थिर, सस्ती आवासीय व्यवस्था के साथ सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ेंगे।

Navbharat Times • 20 Dec • Dharavi

Dharavi's ineligible families will become house owners after 25 years

5 • PG

35 • Sqcm

39749 • AVE

380K • Cir

Top Center

Mumbai

धारावी के अपात्र परिवार 25 साल बाद बनेंगे घर के मालिक

■ प्रसं, मुंबई : एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में रहने वाले अपात्र परिवार 25 वर्ष बाद घर के मालिक होंगे। पुनर्विकास योजना के तहत सरकार ने झोपड़पट्टी के ऊपरी मंजिल में रहने वाले परिवारों को धारावी के बाहर 300 वर्ग फीट का किराया का घर देने की योजना बनाई है।

धारावी पुनर्विकास योजना (डीपीआर) के मुताबिक, किराया पर रहने वाले परिवार 25 साल बाद उस घर का मालिक होंगे। जल्द ही सरकार द्वारा घरों का किराया तय किया जाएगा। इसके साथ ही अपात्र परिवारों को एक और विकल्प मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत अपात्र परिवार घर की कीमत चुकाकर 25 साल के पहले भी घर का मालिक बन सकता है। सरकार द्वारा घर की कीमत तय की जाएगी।

Mid Day (Gujarati) • 20 Dec • Dharavi

In Dharavi redevelopment, upper floor residents will also get space

1, 10 • PG

208 • Sqcm

166727 • AVE

389.96K • Cir

Bottom Center, Bottom Right

Mumbai

મૂંપડપટ્ટી પુનર્વસન યોજનામાં ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ધારાવી રીડેવલપમેન્ટમાં ઉપરના માળવાળાઓને પણ મળશે જગ્યા જોકે 300 સ્ક્વેરફુટનું એ ઘર ધારાવીમાં નહીં હોય અને ૨૫ વર્ષ સુધી એનું સામાન્ય ભાડું ભરવાનું રહેશે

ધારાવી રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ (DRP)માં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની ઉપરના માળ પર રહેતા લોકોને પણ પાત્ર (કાયદેસર) ગણીને તેમને ઘર આપવાની યુનિક પોલિસીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય લઈને DRPમાં બધાને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. મૂંપડપટ્ટીઓના પુનર્વસન માટે આ ઐતિહાસિક નિર્ણય માનવામાં આવી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે મૂંપડપટ્ટી પુનર્વસન યોજનામાં ઉપરના માળને ગેરકાયદે જણવામાં આવે છે અને એને યોજનામાંથી >> 10



આ સ્કીમ હેઠળ ધારાવીના લોકોને પ્રાઇવેટ ટોઇલેટ અને કિચન સહિતની તમામ જરૂરી એમિનિટીઝ મળશે જેનાથી તેમના ગુપ્તગૃહોમાં પણ સુધારો થશે. જે બિલ્ડિંગમાં પુનર્વસન કરવામાં આવશે એને દસ વર્ષ સુધી બિલ્ડર મેઇન્ટેનન્સ કરશે જેથી રહેવાસીઓ પર આર્થિક ભાર ન આવે.
- DRPના અધિકારી

ઝૂંપડપટ્ટી પુનર્વસન યોજના

01► બાકત રાખવામાં આવતા હોય છે. એને લીધે તેઓ બીજે ગેરકાયદે ઝૂંપડ બનાવીને વસતા હોવાથી એનો સ્તરો કાઢવા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

૪ ઓક્ટોબરે આ બાબતે બહાર પાડવામાં આવેલા ગવર્નમેન્ટ રેઝોલ્યુશન (GR) મુજબ ૨૦૨૨ની ૧૫ નવેમ્બર સુધીના તમામ ઉપરના માળને આ યુનિક સ્કીમ માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે. આ યોજનાને હાયર-પર્યેઝ સ્કીમ નામ આપવામાં આવ્યું છે જેમાં દરેક ટેનામેન્ટની સામે ધારાવીની બહાર પણ મુંબઈમાં જ ૨૫ વર્ષના સામાન્ય ભાડા પર ૩૦૦ સ્કવેરફુટની રૂમ આપવામાં આવશે. ૨૫ વર્ષ બાદ એ જગ્યા ટેનામેન્ટ ધરાવનારી વ્યક્તિની માલિકીની થઈ જશે. જો કોઈ વ્યક્તિ એ પહેલાં જ જગ્યાની માલિક બનવા માગતી હોય તો તેણે એક જ વખતે ટ્રિચ રકમ ભરવાની રહેશે. જોકે વ્યાજ અને જગ્યા ખરીદવા માટે કેટલા રૂપિયા આપવાના એ રાજ્ય સરકાર નક્કી કરશે.

શરતો લાગુ

GRમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જે લોકો પાસે ઉપરના માળનું ઈલેક્ટ્રિસિટી બિલ, સેલ અથવા રેન્ટનું રજિસ્ટર્ડ એગ્રીમેન્ટ, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ફ્લોર લખેલો પાસપોર્ટ અથવા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરના માલિકનું સર્ટિફિકેટ એફિડેવિટ હશે તે જ આ હાયર-પર્યેઝ સ્કીમમાં પાત્ર ગણાશે.

In the Dharavi Redevelopment Project (DRP), a historic decision has been made to include upper floor occupants in the rehabilitation scheme. They will receive 300 square feet of space, pay rent for 25 years, and benefit from improved amenities like private toilets and kitchens. Builders will maintain the buildings for ten years.

Janmabhumi • 20 Dec • Dharavi
Relief to upper floor residents in Dharavi

8 • PG

252 • Sqcm

100672 • AVE

34.89K • Cir

Top Center

Mumbai

ધારાવીમાં ઉપરના માળે રહેતા લોકોને રાહત

ધારાવીની બહાર, પચીસ વર્ષ માટે નજીવા ભાડા પર ૩૦૦ ચોરસ ફૂટનું ઘર મળશે

મુંબઈ, તા. ૧૯ : રાહત રહેવાના સુધી ધારાવીમાં રહેવાની હેઠળની આ પ્રકારની સોંપણી પહેલાં, ધારાવી રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટને મકાનના ઉપરના માળના રહેવાસીઓને સમાવવા માટે એક નવો નીતિ અપનાવી છે, જે મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં સૌથી સમાવેશક અને માનવ-કેન્દ્રિત રિડેવલપમેન્ટ યોજના છે.

પરંપરાગત રીતે, ઝૂંપડપટ્ટીમાં ઉપરના માળના રહેવાસીને ગેરકાયદેસર ગણવામાં આવે છે અને તેને ઝૂંપડપટ્ટી પુનર્વસન પ્રોજેક્ટમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે. આના કારણે ઘણીવાર કોઈ વિકલ્પ ન હોવાથી રહેવાસીઓ તબક્કા ધરવિહોણા બની જાય છે. આ ઉપરના માળે વસેલા રહેવાસીઓ ઘણીવાર અન્ય ઝૂંપડપટ્ટીમાં સ્થળાંતર કરે છે, નવા ગેરકાયદેસર બાંધકામો બનાવે છે અને વિસ્થાપનનું ચક્ર ચાલુ રહે છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા અને ઝૂંપડપટ્ટીમુક્ત મુંબઈની દિશામાં આગળ વધવા માટે, રાજ્ય સરકારે ધારાવી પુનર્વિકાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ વિચારશીલ વ્યૂહરચના ઘડી છે, જે માં ઉપરના માળના રહેવાસીઓમાં રહેતા લોકો માટે પણ રહેવાની જોગવાઈઓ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.

૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ના જારી કરાયેલા સરકારી ઠરાવ મુજબ, ૧૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૨ સુધી ધારાવીમાં ઉપરના માળે વસેલા તમામ મકાન ધારકો ભાડા-ખરીદી યોજના પર પુનર્વસન માટે લાયક છે. આ યોજના હેઠળ, મકાન ધારકોને ૨૫ વર્ષ માટે નજીવા ભાડા પર મુંબઈમાં ૩૦૦ ચોરસ ફૂટનું ઘર મળશે, પરંતુ તે ધારાવીની બહાર હશે. ૨૫ વર્ષ બાદ તેઓ યુનિટ (રહેઠાણ)ની માલિકી મેળવશે. આ નીતિ સુગમતા પણ પ્રદાન કરે છે, જેના પગલે રહેવાસીઓ ૨૫ વર્ષના સમયગાળામાં કોઈપણ સમયે એક નિશ્ચિત રકમ ચૂકવીને યુનિટની માલિકી માટે હકદારી સુનિશ્ચિત કરી શકે છે. ભાડું અને યુનિટ ખરીદીની રકમ પ્રોજેક્ટ ઓથોરિટી/ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી અને એકત્રિત કરવામાં આવશે.

ઠરાવમાં જણાવાયું છે કે હકત ઉપરના માળના રહેવાસીઓ જે વીજળી બિલ, રજિસ્ટર્ડ વેચાણ અથવા ભાડા કરાર, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ક્લોસિંગ ઉલ્લેખ કરતા પાસપોર્ટ અથવા લાયક ગ્રાઉન્ડ ક્લોસિંગ રહેવાસી દ્વારા પ્રમાણિત સોગંદનામું રજૂ કરશે, તેઓ જ ભાડા-ખરીદી યોજના માટે લાયક કરશે.

‘ભાડા-ખરીદી યોજના હેઠળ, ધારાવીકર ખાનગી શોચાલય અને રસોડા જેવી આવશ્યક સુવિધાઓ સાથે આધુનિક આવાસોમાં સ્થળાંતર કરશે, જેના પગલે તેમને ગોરવ, ગોપનીયતા અને જીવનની વધુ સારી ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત થશે.’ એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. પુનર્વસન પછી ૧૦ વર્ષ સુધી ઉવલપર દ્વારા ઇમારતોની જાળવણી કરવામાં આવશે, જેનાથી રહેવાસીઓ પર નાણાકીય બોજ ઓછો થશે. વધુમાં, ઇમારતોના બિલ્ટ-અપ વિસ્તારના ૧૦ ટકા વિસ્તારને કોમર્શિયલ ઉવલપ કરવામાં આવશે, જે હાઉસિંગ સોસાયટીઓ માટે કાયમી આવકનો સ્રોત બનાવશે. આધુનિક ટાઉનશીપમાં પહોળા રસ્તાઓ, બાગ-બગીચા, આરોગ્યસંભાળ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને બાળકો અને પરિવારો માટે રમવાગમત અને મનોરંજનની જગ્યાઓ હશે.



Under the Dharavi Redevelopment Project, upper-floor residents will receive 300 square feet of housing outside Dharavi at nominal rent for 25 years. After 25 years, they will own the unit. The scheme offers modern housing with amenities and ensures long-term financial relief and improved quality of life.

 Online Coverage

No	Portal Name	Headline (Incorporated with URL)	Reach
1.	Ndtv	Upper Floor Residents Get Relief In Dharavi Project	111.1M
2.	Prokerala.com	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	13M
3.	Latestly	⚡ Upper-Floor Residents Included in Rehabilitation Scheme	7.8M
4.	Latestly	Mumbai: Dharavi's Upper-Floor Residents Included in Slum Rehabilitation Authori ...	7.8M
5.	Daijiworld	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	3M
6.	Social News XYZ	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	415.2K
7.	Sakshipost EN	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	160.8K
8.	Hindi Business Standard	खराब क्वालिटी वाले जूतों का दौर होगा खत्म, 2025 से आएंगे BIS मानक वाले भारतीय सा...	133.9K
9.	Ommcom News	Dharavi's Upper-Floor Residents Included In Rehabilitation Scheme	133.2K
10.	Lokmattimes.com	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	94.3K
11.	New Kerala	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	72K
12.	Awaz The Voice	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	68.3K
13.	Bhaskar Live	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	46.5K
14.	Gujarati News	ધારાવીમાં ઉપરના માળે રહેતા લોકોને રાહત	26.1K
15.	OB News	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	N/A
16.	The Mobi World	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	N/A
17.	Today News 24	Mumbai: Dharavi's Upper-Floor Residents Included in Slum Rehabilitation Authori ...	N/A
18.	Bilkul	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	N/A
19.	Today India News	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	N/A
20.	Thefreedompress	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	N/A
21.	Pune News	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	N/A
22.	India Online Mart	Dharavi's upper-floor residents included in rehabilitation scheme	N/A
23.	Awaaz Hindi	धारावी के ऊपरी मंजिल के निवासियों को पुनर्वास योजना में शामिल किया गया	N/A
24.	News89	Upper Floor Residents Get Relief In Dharavi Project	N/A
25.	Free Press Journal	निर्जंतुकीकरण केलेले ५० टक्के पाणी पिण्यासाठी वापरणार; पाण्याची गरज भागवण्यासाठी...	N/A